नईदुनिया

अमेरिका से गुप्त डील करने पर पाकिस्तान को मिली थी आईएमएफ से रहम, तीन अरब डॉलर का सच जानकर रह जाएंगे हैरान

वाशिंगटन ।

पाकिस्तान की बिगड़ते आर्थिक हालातों से कोई अनजन नहीं है। आए दिन अन्य देशों के सामने हाथ फैला देता है। इसी क्रम में, पाकिस्तान अपने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए हर किसी से रहम की मांग कर रहा था। तभी, जुलाई में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए तीन अरब डॉलर वाले राहत पैकेज का एलान किया। इससे वहां के लोगों के चेहरे खिल गए। हालांकि, अब इसी मदद को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उसे यह मदद अमेरिका के साथ हुई एक गुप्त डील के तहत मिली थी।

यह थी डील – दो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने गुप्त हथियारों की खरीद के बदले इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के लिए आईएमएफ बेलआउट पैकेज की एक डील सुरक्षित की थी। यह डील यूक्रेन की सेना को हथियारों की सप्लाई के मकसद से जुड़ी थी। एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान और अमेरिका के सरकारी दस्तावेजों की पुष्टि करने वाले सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

जनता को कुछ पता नहीं लगता – रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान को किस कदर अमेरिका से दबाव का सामना करना पड़ा था। क्योंकि हथियारों की बिक्री यूक्रेनी सेना की आपूर्ति के उद्देश्य से की गई थी। आगे कहा गया है कि इससे यह भी पता लगता है कि कैसे राजनीतिक और फाइनेंस से जुड़ा एलीट वर्ग छिपकर काम करता है। इसके बारे में कभी जनता को कुछ पता नहीं लग पाता है।

रखी गई कठोर शर्तें – अमेरिका की एक मीडिया ने यह भी बताया कि आईएमएफ की तरफ से मिले बेलआउट पैकेज में कुछ कठोर शर्तें रखी गई हैं, जिसकी वजह से देश को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। देश में कई हड़तालें हुईं। यह विरोध प्रदर्शन देश में डेढ़ साल से चल रहे राजनीतिक संकट का ताजा अध्याय है। दावा किया गया कि इमरान ने जाने से पहले विदेश मंत्रालय में राजनयिकों के सामने यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान के आक्रामक तटस्थ रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। उनके जाने के बाद से यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान, अमेरिका और उसके साथियों का समर्थक बन गया है। उसकी मदद को अब आईएमएफ के कर्ज के तौर पर चुकाया जा रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले आपातकालीन कर्ज ने नई पाकिस्तानी सरकार को आर्थिक तबाही से बचने और चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टालने की अनुमति दी।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका-चीन जासूसी नेटवर्क बढ़ा रहे: लीडर्स की सोच और फौजी क्षमता पर नजर; एक-दूसरे की जानकारी जुटाने हाई लेवल सिस्टम बनाया

वॉशिंगटन । अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पता लगा है कि फरवरी में अमेरिकी समुद्र तट के पास आए

चीन के जासूसी गुब्बारे के संबंध में राष्ट्रपति शी जिन पिंग को पहले से जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस पर सीनियर फौजी जनरलों पर गुस्सा भी जताया था। शी अमेरिका के खिलाफ जोखिम भरे जासूसी अभियानों के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन, जब उन्हें अहसास हुआ कि बैलून कांड से अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से बातचीत प्रभावित होगी तब उन्होंने सीनियर जनरलों की खिंचाई की थी। यह घटना अमेरिका और चीन के बीच गुप्त जासूसी मुकाबले के विस्तार पर रोशनी डालती है। बैलून संकट अमेरिका के खिलाफ चीन के बेखौफ और आक्रामक जासूसी प्रयासों की झलक दिखाता है। वहीं इसके साथ चीन के संबंध में जानकारी जुटाने की अमेरिका की बढ़ती क्षमता का खुलासा भी होता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की सोच है, अमेरिका की ताकत के लिए चीन लंबे समय में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए वे उसकी सैनिक और तकनीकी क्षमता पर काबू पाना चाहते हैं। दूसरी ओर चीनी खुफिया एजेंसियों का दुस्साहस शी की योजना का हिस्सा है। उन्होंने देश की सीमाओं पर आक्रामक रुख अपनाया है। चीन और अमेरिका ने दुनियाभर में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक्टिव होने के निर्देश दिए हैं। इसकी दो मुख्य वजह हैं जासूसी अभियान के बारे में अधिकतर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, फोकस ताइवान के संबंध में चीन के इरादों पर है। एफबीआई ने अमेरिका के अंदर जासूस भर्ती करने के चीनी प्रयासों की खोज पर ध्यान दिया है। अमेरिकी एजेंटों ने पिछले एक साल में अमेरिका की धरती पर फौजी अड्डों में चीनी नागरिकों की एक दर्जनों घुसपैठ का पता लगाया है। दोनों देश अपनी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से कर रहे हैं। इससे फौजी, आर्थिक सर्वोच्चता बनाए रखने के साथ उनकी खुफिया एजेंसियों को नई धार मिलेगी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, चीन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा, डिप्लोमेसी और आधुनिक कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी के हर पहलू पर नजर रखता है। पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चीन की जासूसी पर फोकस करने वाले नए सेंटर बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को खोजने की क्षमता बेहतर की गई है। चीन की समुद्री सीमा के पास जासूसी विमानों की हलचल बढ़ाई है। एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे कहते हैं, चीन से जासूसी टकराव शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुए टकराव से अधिक व्यापक है।

कई लोगों का मानना कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र में काफी छोटा', आलोचनाओं पर बोले विवेक रामास्वामी

वाशिंगटन । भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने कहा कि कई लोग मेरे आगे बढ़ने से नाराज हैं और उनका मानना है कि 38 वर्षीय व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटा है। दरअसल, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की पहली प्राथमिक बहस के दौरान रामास्वामी के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद विभिन्न जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। नवीनतम जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि वह अगस्त के प्रदर्शन से 12 अंक ऊपर हैं। साथ ही उनके विरोधियों द्वारा उनकी आलोचना भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। रामास्वामी ने एक स्थानीय मीडिया से कहा कि देखिए जब से मैंने दूसरी बहस में अच्छा प्रदर्शन किया है, तबसे ही कड़ी आलोचना की जा रही है। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए खुली बहस के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि कई लोग मेरे आगे बढ़ने से नाराज हैं और मानते हैं कि 38 साल का व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तथ्य यह है कि थॉमस जेफरसन 33 वर्ष के थे, जब उन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा था। उन्होंने कहा कि इसी भावना को आज फिर से जगाने की जरूरत है। रामास्वामी ने कहा मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति के जीवन में अभी भी सबसे अच्छे दिन बाकी हों, उसे एक ऐसा देश देखना होगा, जिसके सबसे अच्छे दिन अभी बाकी हों। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी हमारे सबसे अच्छे दिनों को देख सकता है, लेकिन हम किसी चीज से भाग नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में बाइडन के कट्टरपंथी एजेंडे की ज्यादा आलोचना नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि यह ध्यान केंद्रित करने के लिए गलत जगह है। बेशक, आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपनी खुद की एक दृष्टि पेश करनी होगी, न कि सिर्फ यह कि हम किससे भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बुनियादी मुद्दे हैं, जिनपर हम बहस कर सकते है और इस बात से ज्यादातर अमेरिका के लोग भी सहमत होंगे। यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि हमारे पास 1980 की शैली, रोनाल्ड रीगन-शैली, नैतिक जनादेश देने का मौका है। इस तरह हम इस देश को एकजुट करेंगे और मैं इस दौड़ में हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वाला उम्मीदवार हूं।

भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को काउंटर करने की तैयारी में तुर्किये

इराक, कतर और यूएई के साथ बनाएगा दूसरा ट्रेड रूट ; 14 लाख करोड़ खर्च होंगे

अंकारा ।

भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल नहीं किए जाने से नाराज तुर्किये इस अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रूट का विकल्प खोज रहा है। कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए तुर्किये एक नए ट्रेड रूट की घोषणा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर तुर्किये ने इराक, कतर और यूएई से बात की है। तुर्किये के कॉरिडोर को इराक डेवलपमेंट रोड इनिशिएटिव नाम दिया जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए इराक के ग्रैंड फॉ पोर्ट से तुर्किये में आसानी से सामान लाया और ले जाया जा सकेगा। इस पर 14 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ये 1200 किलोमीटर लंबा ट्रेड रूट होगा। इसके पहले फेज को 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

एक्सपर्ट्स ने तुर्किये को चेताया

एक तरफ जहां तुर्किये इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है, वहीं एक्सपर्ट इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। यूरेशिया ग्रुप थिंक-टैंक के निदेशक एमरे पेकर कहते हैं कि तुर्किये के पास परियोजना को साकार करने के लिए पैसे की कमी है। ऐसा लगता है कि वो बुनियादी ढांचे के लिए यूएई और कतर के सहारे है। खाड़ी देशों से पैसे लेने के लिए तुर्किये को उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि इस रूट में निवेश करने से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। पेकर के मुताबिक सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दे भी हैं, जो तुर्किये की परियोजना को खतरे में डाल सकते हैं। इराक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, खस्ताहाल बुनियादी ढांचे, कमजोर सरकार और नियमित राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। यह भी साफ नहीं है कि इराक इस परियोजना में पैसा कैसे लगाएगा। इराक मध्य पूर्व का वो हिस्सा है जो हिंसा और अस्थिरता से घिरा रहता है। जिस बसरा में इस प्रोजेक्ट का सपना देखा जा रहा है वह कभी आईएसआईएस का गढ़ था। यहां के युवाओं पर अभी तक आईएसआईएस का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे में एर्दोगन जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसका भविष्य भी खतरनाक हो सकता है।

राष्ट्रपति एर्दोगन बोले- हमारे बिना पूर्व से पश्चिम नहीं जा सकते

भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था कि उनके बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले किसी भी ट्रैफिक को तुर्किये से होकर गुजरना ही होगा। दरअसल, जी20 समिट में जिस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई वो भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन से होते हुए गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट का फायदा इजराइल और जॉर्डन को भी मिलेगा। हालांकि तुर्किये और मिस्र को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है।

मुंबई से शुरू होकर कॉरिडोर यूरोप तक जाएगा

मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6 हजार किमी लंबा होगा। इसमें 3500 किमी समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40 प्रतिशत समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं, इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात-निर्यात आसान और सस्ता होगा।

सात वजहों से भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ा

सबसे पहले भारत और अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार दोनों मिडिल ईस्ट में साझेदार बने हैं। भारत की मध्य एशिया से जमीनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान का तोड़ मिल गया है। वह 1991 से इस प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहा था। भारत के ईरान के साथ संबंध सुधरे हैं, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान से यूरेशिया तक के रूस-ईरान कॉरिडोर की योजना प्रभावित होती जा रही है। अरब देशों के साथ की भागीदारी बढ़ी है, यूएई और सऊदी सरकार भी भारत के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब प्रायद्वीप में राजनीतिक स्थिरता आएगी और संबंध सामान्य हो सकेंगे। यूरोपीय यूनियन ने 2021-27 के दौरान बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए 300 मिलियन यूरो निर्धारित किए थे। भारत भी इसका भागीदार बना। नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है। कई देशों को चीन के कर्ज जाल से मुक्ति मिलेगी। जी-20 में अफ्रीकी यूनियन के भागीदार बनने से चीन और रूस के अफ्रीकी देशों में बढ़ती दादागीरी को रोकने में मदद मिलेगी।

उन्हें किस्मत का साथ मिले

रिपब्लिकन पार्टी ने की महाभियोग चलाने की तैयारी, राष्ट्रपति बाइडन ने उड़ाया मजाक

वॉशिंगटन ।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की आशंकाओं का मजाक उड़ाया। दरअसल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैक्कार्थी ने बीते हफ्ते जो बाइडन के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडन के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। जब इसे लेकर जो बाइडन से सवाल किया गया तो उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी पर तंज कसा। बाइडन ने कहा कि उन्हें किस्मत का साथ मिले।

जो बाइडन पर लगे हैं ये आरोप

बता दें कि केविन मैक्कार्थी ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति बाइडन के खिलाफ कई गंभीर और विश्वसनीय आरोपों का खुलासा किया है। जिसकी जांच चल रही है। आरोप जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन के बेटे के विदेशी व्यापार को लेकर लगे हैं। हालांकि अभी तक जांच का दायरा साफ नहीं है। वहीं राष्ट्रपति बाइडन ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी हंटर बाइडन के व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार को लेकर बात नहीं की। बीते हफ्ते जब बाइडन से इस बारे में सवाल किया गया था तब बाइडन ने कहा था कि कट्टरपंथी रिपब्लिन पार्टी के नेता उनके खिलाफ महाभियोग चलाना चाहते हैं और सरकार को बंद करना चाहते हैं।

जो बाइडन को महाभियोग से हटाना मुश्किल

हालांकि जो बाइडन को महाभियोग से हटाना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका में महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पूरे हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स का वोट करना जरूरी है। इसके बाद सीनेट में इस पर बहस होगी और यहां वोटिंग के बाद तय होगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ लगे आरोप सही हैं या नहीं। उसके बाद ही राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दो बार महाभियोग लाया गया था। हालांकि दोनों ही बार वह विफल रहा।

संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ में मारे गए लोगों की संख्या में किया बदलाव, अभी भी बढ़ सकता है आंकड़ा

डेर्ना ।

संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की बाढ़ में मारे गए लोगों के आंकड़े में पहले के मुकाबले संशोधन किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया के डेर्ना शहर में आई बाढ़ में 3958 लोगों की जान गई है। बता दें कि पहले संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर कॉर्डिनेशन ऑफ ह्युमैनिटेरियन अफेयर्स विभाग ने मृतकों का आंकड़ा 11,300 बताया था। संयुक्त राष्ट्र ने ताजा आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 9000 लोग अभी भी लापता हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने बताई संशोधन की वजह

संयुक्त राष्ट्र ने पहले लीबियाई रेड क्रीसेंट के हवाले से मृतकों का आंकड़ा 11,300 बता दिया था। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल फरहान हक ने बताया कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताए गए आंकड़े की भी पुष्टि कर रहे हैं। वहीं लीबियाई रेड क्रीसेंट ने कहा कि उन्होंने कभी भी मृतकों का इतना बड़ा आंकड़ा जारी नहीं किया था। फरहान हक ने बताया कि दुनिया में कई जगह हो रहीं त्रासदियों की वजह से उन्हें अपने आंकड़ों में संशोधन करना पड़ रहा है और इसी वजह से यह कन्फ्यूजन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि लीबिया की बाढ़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा अभी भी बदल सकता है।

दुनियाभर से मिल रही लीबिया को मदद

वहीं बाढ़ के बाद लीबिया के डेर्ना में राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स से समुद्र में शवों की तलाश की जा रही है। डेर्ना की जनसंख्या करीब 1,20,000 है और बाढ़ के चलते लगभग पूरा शहर बह गया था। बताया जा रहा है कि शहर के दक्षिण में स्थित दो बांधों के टूटने के चलते यह बाढ़ आई और लोगों को अपने साथ बहाकर ले गई। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि लीबिया की मदद के लिए सात करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद चाहिए होगी और इसके लिए उसने दुनियाभर के देशों से अपील की है। डब्लूएचओ ने पूर्वी लीबिया में रहने वाले करीब ढाई लाख लोगों के लिए आपातकालीन सहायता भेजी है। इनमें जरूरी दवाएं, सर्जरी सप्लाई और शवों को ढकने वाले बैग भेजे गए हैं।

ताइवान में 103 चीनी विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की: 24 घंटे में 9 युद्धपोत भी घुसे; चीन के विदेश मंत्री से मिले अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर

ताइपे ।

ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को दावा किया है कि 24 घंटे में चीन के 103 जंगी विमानों ने उनके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी घुसपैठ बताया है। ताइवान ने कहा है कि ऐसा कर चीन इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन लगभग हर रोज ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता है। हालांकि, सोमवार के बीच चीन के 40 वॉरप्लेन दोनों देशों के बीच बनी मीडियन लाइन पार करते हुए ताइवान में घुसे। इससे पहले शनिवार और रविवार के बीच 63 प्लेन ताइवान में घुसे थे। इनके अलावा 9 युद्धपोतों ने भी ताइवान के एरिया में एंट्री ली। चीन की तरफ से ये घुसपैठ उस समय की गई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दो दिन की मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया।

चीन-अमेरिका ने यूक्रेन, ताइवान पर चर्चा की

जासूसी बैलून के बाद रिश्तों में आए तनाव को दोनों देश दूर करना चाहते हैं। ऐसे में जेक सुलिवन और वांग यी के बीच हुई बातचीत को अहम माना जा रहा है। हालांकि, दोनों के बीच क्या चर्चा हुई अभी इसकी डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। व्हाइट हाउस ने बताया है कि दोनों के बीच यूक्रेन जंग, ताइवान और ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दों पर चर्चा की गई। चीन ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में ताइवान वो रेड लाइन है, जिसे अमेरिका क्रॉस नहीं कर सकता है।

चीन ने ताइवान को कब्जाने का ब्लूप्रिंट जारी किया था

पिछले हफ्ते ही चीन ने ताइवान पर कब्जा कर उसे अपने में मिलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया था। इसके लिए वो तटीय क्षेत्र फुजियान और ताइवान के बीच दूरियां कम करना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी और स्टेट काउंसिल ने ताइवान पर कब्जे और उसके बाद वहां अपनी सत्ता जमाने के लिए फुजियान को प्रैक्टिस जोन बनाया। करीब 1 महीने पहले चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ताइवान पर हमले के लिए ट्रेनिंग करते नजर आए थे। पीएलए के 96 साल पूरे होने पर चीन ने स्टेट मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इसका नाम झू मेंग या चेसिंग ड्रीम्स था।

अमेरिका-चीन की ताइवान पर भिड़ने की वजह

अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए। इसके बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। चीन को इस पर ऐतराज है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसकी नीति नहीं है।

सऊदी-इजराइल बैकडोर बातचीत बंद

नेतन्याहू के फिलिस्तीन पर रुख से क्राउन प्रिंस सलमान नाराज, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था

तेल अवीव/रियाद ।

सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू कराने की अमेरिकी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब और इजराइल की बैकडोर बातचीत सस्पेंड हो गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की कट्टरपंथी सरकार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है कि फिलहाल बातचीत जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। इजराइल के रवैये से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाराज बताए जाते हैं।

सऊदी ने अमेरिका को जानकारी दी – इजराइली अखबार की रिपोर्ट में सऊदी अरब के अखबार के एक आर्टिकल का हवाला भी दिया गया है। इसके मुताबिक- अमेरिका ने नेतन्याहू सरकार को सऊदी सरकार की नाराजगी के बारे में बता दिया है। नेतन्याहू सरकार में मंत्री बेजेल स्मॉट्रिच और इटमान बेन गिविर के हालिया बयानों को बातचीत टालने का आधार बनाया गया है। इन दोनों ही मंत्रियों ने पिछले दिनों इजराइल के कब्जे वाले इलाके का दौरा किया था और वहां दो टूक कहा था कि नेतन्याहू सरकार किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को कोई राहत नहीं देगी। खुद नेतन्याहू ने भी पिछले महीने कहा था- हम सबसे खुले दिमाग से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी गठबंधन सरकार है, लिहाजा सहयोगी पार्टियों की बात सुनना भी जरूरी है। अगर दोनों पक्ष चाहें तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य किए जा सकते हैं।

सऊदी अमन चाहता है – यूएन में इसी हफ्ते जनरल असेंबली का सेशन होना है। सऊदी अरब सरकार इस असेंबली के बाद एक इवेंट ऑर्गनाइज कर रही है। इसके मकसद है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को हमेशा के लिए हल किया जा सके और इसमें तमाम देश एक मंच पर आकर कोशिश करें। हालांकि, नेतन्याहू कैबिनेट के कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मिनिस्टर्स फिलिस्तीन या सऊदी अरब से कोई समझौता नहीं करना चाहते। यही वजह है कि अरब में अमन की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में नई दिल्ली जी-20 में शिरकत की थी। तब उन्होंने कहा था कि सऊदी अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेगा, जिसके जरिए अरब वर्ल्ड में हमेशा के लिए अमन कायम हो सके। इजिप्ट और जॉर्डन भी इसमें रोल प्ले करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पहले ही सऊदी पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी इस हफ्ते यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इसी दौरान नेतन्याहू भी यहां मौजूद होंगे। बहुत मुमकिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों से अलग-अलग मुलाकात करें और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अगर फिलिस्तीन और इजराइल कुछ बातों पर सहमत हो जाते हैं तो सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं होगी।

सऊदी पर अमेरिकी दबाव – दो महीने पहले अमेरिका ने पहली बार खुलकर कहा था कि वो इजराइल और सऊदी अरब में नॉर्मल रिलेशनशिप चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था- अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मल रिलेशन हों। अमेरिका को इससे काफी फायदा है। इस टारगेट को हासिल करने में कुछ वक्त और लग सकता है। ब्लिंकन के इस बयान के वर्ल्ड डिप्लोमैसी में बेहद अहम मायने हैं। इजराइल सरकार ने हाल ही में माना था कि सऊदी से बैकडोर डिप्लोमैसी के तहत बातचीत जारी है और अमेरिका मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है।